SHRI VENOD SHARMA: Is it a fact that the degradation of the fragile eco-system in the North-Western Himalayas poses a grave danger to the entire plain areas and could result in desert-like conditions? Secondly, is there a proposal for constituting a North-Western Himalyas Eco-Development Authority for the eco-development of the entire North-Western Himalayas region? And looking into the urgency of the matter, is there any time-frame to set up an authority? Will the Minister please answer these questions?

SHRI SUKH RAM: I appreciate and associate myself with the concern expressed by the hon. Member for desertification of the plain areas, particularly in Punjab, Haryana and major parts of UP.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Do you just appreciate or share his concern?

SHRI SUKH RAM: I appreciate and also share his concern. This soil erosion problem is becoming very acute in the North-Western Himalayas i.e. in Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and UP Hills. For that purpose, as I have just now stated, an eco-development authority is proposed to be set up under the Chairmanship of the Prime Minister. In case we do not attend to this problem, as per the report of Dr. Swaminathan, who is supposed to be an expert on Himalayan problems, then Punjab, Haryana and major parts of UP, including Delhi, will face the same situation, which North Bihar is facing now. I cannot give the time-frame about this proposal, because it concerns other departments e.g. Department of Environment. I will ensure that a speedy action is taken. As far as the constitution of the authority is concerned, and whatever action is needed in this behalf, I will do my best.

Export and development of handicrafts of Bihar

*523. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the handicrafts of the State of Bihar are in great demand abroad;

(b) if so, what are the details of export of handicrafts from Bihar during the last three years;

(c) whether Government gives any incentives to the producers of handicrafts in the State;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what action Government propose to take for the development of handicrafts in Bihar?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The handicrafts items from India, including Bihar have a good market abroad. Statewise statistics of export are not maintained.

(c) and (d) The Government of India recognises outstanding skills among craftspersons. As an incentive to all craftspersons including those from Bihar, there is a scheme of National Awards and Merit Certificates. Under this scheme since its inception in 1965, 17 master craftspersons from Bihar have been given National Awards and 19 craftspersons have been given Merit Certificates.

Under a scheme of financial assistance to craftspersons in indigent circumstances, 13 master craftspersons from Bihar have been given financial assistance of Rs. 500 per month.

(e) Although handicrafts is a State subject, in order to encourage the development of handicrafts in Bihar, the Government of India through the Development Commissioner (Handicrafts) has taken various steps to encourage their production. These include programmes of training in various crafts, design and technological development, marketing development and support, and establish-

ment of craft development centres for providing integrated services to crafts-persons.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उप-सभापति महोदया, बिहार के हस्त शिल्प सहित और जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं वे विदेशों में निर्यात करने के लिए तरह तरह की संस्थाओं के माध्यम से निर्यात किये जाते हैं। इसमें भारत सरकार की एक संस्था है हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड। महोदया, जब से यह संस्था बनी है यह विभिन्न राज्यों से निर्यात करने के लिए जो हस्त शिल्प की वस्तुएं लेती हैं और उनको सैम्पुल्स के रूप में ले जाकर विभिन्न विदेशी संस्थाओं से आर्डर लाती हैं। उसके बाद आर्डर को फुलफिल करने के लिए दूसरी संस्थाओं को आर्डर दे दिया जाता है। उसमें बिहार को वंचित रखा जाता है—"क" और "ख"—महोदया, मेरा यह कहना है कि द हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने अपने हैम्बर्ग स्थित दफ्तर में जो कारपेट डिवीजन है जहां कि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और काश्मीर के कालीन जाते हैं उस कारपेट डिवीजन के दफ्तर को रिजर्व बैंक आफ इंडिया से पूछे बगैर जेद्दा में ट्रांसफर कर दिया है और जेद्दा में करीब एक करोड़ रुपये ज्यादा के कालीन इन्होंने बिना रिजर्व बैंक आफ इंडिया से परमिशन लिये वहां भेज दिये और मिट्टी के भाव बेच डाले—और भी बहुत सी चीजें बेचीं—जिससे कि करीब सवा करोड़ रुपये का घाटा हुआ। क्या इस पर मंत्री जी कुछ रोशनी डालेंगे कि आखिर किन कारणवश हैम्बर्ग का सामान बिना रिजर्व बैंक की परमिशन से किस अफसर द्वारा, किसके कहने पर वहां जेद्दा भेजा गया और बेचा गया जिससे सरकार को घाटा हुआ और उसके साथ साथ हस्त शिल्पकारियों को भी घाटा हुआ?

श्री अशोक गहलोत : मैडम, माननीय सदस्य ने बिहार के संबंध में क्वेश्चन किया है और एच०एच०ई०सी० के बारे में सवाल उठाये हैं। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि जेद्दा में आफिस नया खोला गया है और उसमें घाटा हुआ है, यह बिल्कुल सही बात है। मैंने इसके लिए मंत्रालय में कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में आर०बी० आई० से बगैर पूछे हुए इस आफिस को खोला गया... (*व्यवधान*) करीब दो साल पहले खोला गया था तो उसकी हम अलग से जांच करवा रहे हैं और जांच पूरी होगी तब बताएंगे... (*व्यवधान*)

श्री एस० एस० अहलुवालिया : अभी आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? जो कन्सर्न्ड आफिसर हैं वे ही उस वक्त हैम्बर्ग में जनरल मैनेजर थे आज वे आपके सी०एम०डी० हैं। आपने उसको निलम्बित क्यों नहीं किया अब तक? बिना आर०बी०आई० से पूछे वह कैसे आफिस जेद्दा ले गये?

उपसभापति : एक एक करके इस से गुस्सा करके सवाल नहीं कीजिए। उनको जवाब देने दीजिए। साधारण तरीके से सवाल पूछिए और जवाब साधारण तरीके से लीजिए।

श्री अशोक गहलोत : इसके लिए मैं कह चुका हूं कि आर०बी०आई० से बिना परमिशन के जब आफिस खोला गया तो यह इस सरकार के बनने के पहले वाली बात है। उसके बावजूद भी इसकी जांच करवाने के लिए मैंने कहा है, कि किन परिस्थितियों में खोला गया। उसकी जांच पूरी होगी तब मैं बता पाउंगा।

जहां बिहार के संबंध में एच०एच०ई० सी० से खरीददारी की बात है, यह कामर्शियल कान्सिडरेशन से काम करता है। माननीय सदस्य अगर कोई विशेष बात बताएंगे कि किन किन आइटम्स को खरीदने के आफर हुए हैं और खरीदा नहीं गया तो उसमें मैं जानकारी कर सकूंगा और कह सकूंगा कि बिहार के सारे वे आइटम खरीदे जाएं जो जरूरी हैं... (*व्यवधान*)

उपसभापति : सेकेंड सप्लीमेंट्री।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उप-सभापति महोदया, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इन्होंने इंक्वायरी बैठायी है।

पर यह दुर्भाग्य की बात है कि जो कन्सर्ड आफिसर हैं वे अभी तक निलम्बित नहीं हुए हैं । वे ही सी०एम० डी० हैं और उनके तहत इक्वायरी क्या होगी . . .

एक माननीय सदस्य : वह जांच को प्रभावित करेगा ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : वह तो जांच को पूरी तरह से प्रभावित करेगा और सच्चाई सामने नहीं आएगी . . .

उपसभापति : वह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : सम्बन्धित है . . . **(व्यवधान)**

नहीं, नहीं, यह हेंडीक्राफ्ट्स कारपोरेशन की बात है । सम्बन्धित है तभी मैं कह रहा हूं . . .

उपसभापति : है तो पूछिए ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उप सभापति महोदया, मैं तो मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा उसके बारे में कि आखिर यह जांच को जो प्रभावित कर रहे हैं वहां के सी.एम.डी. खुद इसमें इन्वाल्व हैं उसके बारे में यह क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा स्कैम है और कई करोड़ों के घाटे में चल रहा है और उसके बावजूद एक आफिसर को प्रोमोट करके सी०एम०डी० बनाकर बैठा दिया गया है, इस पर खोज करने की जरूरत है ? महोदया, साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि दरिद्र अवस्था में सिद्धहस्त शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 500 रुपए मासिक सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का जो प्रोग्राम है उसके क्या-क्या नार्म्स हैं और बिहार में कितने सिद्धहस्त शिल्पकारों को आप इस तरह की सहायता देते है ?

श्री अशोक गहलोत : मैडम, मैंने अपने मुख्य रिप्लाय में कहा है कि 13 लोगों को सहायता मिल रही है और नार्म्स यही हैं कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हो जाते हैं और जिनको नेशनल अवार्ड मिल चुका होता है उन लोगों को हम इस प्रकार की सहायता देते हैं । बिहार में जैसा मैंने लिखा भी है कि 13 लोगों को सहायता मिल रही है और इसके अलावा जो विकलांग हैं उनके ऊपर भी हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं और उनको भी सहायता दी जाती है । जहां तक सी०एम०डी० की बात कही गई, मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि जो सी.एम.डी. अभी बने हैं उसके पहले यह आर.बी.आई. के बिना परमिशन के आफिस वहां पर शिफ्ट हुआ था। जेद्दाह में लगा था और उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई इस इन्क्वायरी को प्रभावित नहीं करे और जो दोषी होगा उसको पूरी सजा दिलवायेंगे ।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदया, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि यह हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट्स का जिसमें बिहार कभी शामिल है विदेशों में अच्छी मांग है । तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बिहार के किस-किस आइटम्ज की विदेशों में अच्छी मांग है, यह हमको बताइये ? इसी से संबंधित है कि मुझे जहां तक मालूम है कि मिथिला पेंटिंग्स जिनकी पहले ज्यादा बिक्री थी अब राजगीर उपेक्षा के कारण घट गई है, नहीं तो पहले इनकी बिक्री ज्यादा हो रही थी । राजगीर और बौधगया की पहाड़ियों से बनी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति की पहले ज्यादा बिक्री हो रही थी, अभी प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण यह भी घट गई है ? तीसरा, जो बिहार का हैंडलूम है उसको तो कोई प्रोत्साहन ही नहीं है जिससे वह वहां जा सके ? इन तीन विषयों के बारे में हम चाहेंगे कि आप क्या जांच करायेंगे और दूसरा बतायेंगे कि और किन-किन वस्तुओं की विदेश में भी ज्यादा मांग हो रही है, यह मैं जानना चाहूंगा ।

श्री अशोक गहलोत : मैडम, जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि बिहार में किन-किन आइटम्स का ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि मधुबनी की पेंटिंग्स की मांग काफी है, सिक्की ग्रास, बंबू क्राफ्ट्स, लैक्कर वेयर्ज, एप्लिक वर्क्स, वुड-वर्क्स, टायर्ज एंड डॉल्ज, पेपर मशे ब्रास एंड बैल मैटल्स वुलन कार्पेट्स एंड दरीज हैंड प्रिंटेड टैक्सटाइल्स स्टोन वर्क्स ज्वैलरी, सभी तरह की आइटम्स

की पूरी मांग है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है।

श्री चतुरानन मिश्र : यह तो हमने बताया कि एक्सपोर्ट घट गया है फिर कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि यह घट गया ?

श्री अशोक गहलोत : यह आपको कैसे मालूम पड़ा कि घट गया ?

श्री चतुरानन मिश्र : आपके पास तो आंकड़े ही नहीं। महोदया, इनके पास आंकड़े ही नहीं हैं। स्टेटवाइस स्टेटिस्टिक्स आफ एक्सपोर्ट आरनाट मैंटेंड फिर कैसे कहेंगे। हम तो जानते हैं इसलिए कह रहे हैं, आप कहां से कह रहे हैं ? . . . (**व्यवधान**) इन्होंने कहा कि स्टेटवाइज स्टैटिस्टिक्स नहीं रख रहे हैं . . . (**व्यवधान**) एक कापी इनको भी भेज दीजिए . . . (**व्यवधान**) अभी हम कह रहे हैं कि जब आपने . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : चतुरानन जी, इनको जवाब तो देने दीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : तो इसलिए हमने कहा कि . . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : हां, तो वह बोल रहे थे, आप बीच में बोल दिए।

श्री चतुरानन मिश्र : नो-नो, इसकी जांच कर रहे हैं या नहीं ?

उपसभापति : बोलने तो दीजिए।

श्री अशोक गहलोत : मैडम, माननीय सदस्य की भावनाओं से मैं सहमत हूं, पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आंकड़े तो रखते हैं पर क्वेश्चन के आंकड़े अलग से नहीं हैं, वरना हमारे पास में ऐसी कोई खबर नहीं है कि बिहार की पर्टिकुलर आइटम्स की एक्सपोर्ट घट गई है। फिर भी अगर आपने यह बात कही है तो मैं उसकी जांच करूंगा कि क्यों घट गई है या घटी या नहीं घटी है, यह फिर मैं आपको बताऊंगा।

श्रीमती कमला सिन्हा : उपसभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी इन्होंने अपने प्रश्न के खंड "बी" में कहा कि 13 मास्टर क्राफ्टसपर्सन को बिहार से इन्होंने 500 रुपया माहवारी सहायता देने का तय किया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि आपने जो सूची पढ़ी उस सूचीके तहत बिहार में कोई ऐसा हैंडीक्राफ्ट नहीं है जो लोग नहीं बनाते हैं ? तो इसके तहत कितने लोग और ऐसे हैं कि जिनको वित्तीय सहायता आवश्यक होगी ? आपने कोई टार्गेट बनाया है ?

कोई मोनिटरिंग की है इस दिशा में ? और, दूसरी बात, मैं यह पूछना चाहती हूं आज पूरे देश में एक नई प्रक्रिया चल रही है कि "लैटस गो बैक टू द पास्ट" जिसको हम कहते हैं एथनिक कल्चर को डवलपमेंट करने की बात रही है और एथनिक वेष-भूषा पहनने की बात हो रही है, छोटा नागपुर में और उत्तरी बिहार के पहाड़ी इलाके में, नेपाल की तराई के इलाके में औरतें पहले जिस तरह का गहना पहना करती थीं, वह आज भी उसी तरह का पहनती हैं, क्या उसके प्रमोशन के लिए भी सरकार ने कोई विशेष ध्यान दिया है ? क्योंकि मुझे यह जानकारी है कि अपने देश की शहरी औरतें उसको पसंद करेंगी और यहां तक कि विदेश में भी उसका एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो मेरे यह दो प्रश्न हैं। कृपया जवाब दीजिए।

श्री अशोक गहलोत : मैडम, माननीय सदस्या ने उत्तरी बिहार में और जो पारंपरिक वेशभूषा की बात की है, . . .

उपसभापति : गहनों की बात, गहने पहनने की बात है।

It is a very important export item.

श्री अशोक गहलोत : जी, गहनों की बात की है। जो इस प्रकार की नई बात की है, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। . . . (**व्यवधान**)

श्रीमती कमला सिन्हा : नहीं, यह हलकी बात नहीं है । . . .

श्री अशोक गहलोत : जो मैडम ने कहा है कि पूरे देश में परंपरागत गहनों में भी जाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो एक अच्छी बात है, उसको हम लोग हर तरह से प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं । इसमें अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप हमें लिखकर भेज सकती है, हम उसके ऊपर पूरा गौर करेंगे ।

उपसभापति : रफीक आलम जी ।

श्रीमती कमला सिन्हा : माननीया, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपने केवल 13 व्यक्तियों को, मास्टर क्राफ्टमैन को वहां इनडिजनस इसको, असिस्टेन्स दे रहे हैं 500/- रुपये प्रतिमाह, तो क्या 13 व्यक्तियों को ही आपने आइडेंटिफाई किया है या और अधिक लोगों की आवश्यकता है ? क्या दूसरे किस-किस वाला में उनको आइडेंटिफाई करके आपने मदद की ? और कितने लोगों की आवश्यकता है ? . . . (**व्यवधान**)

श्री अशोक गहलोत : मैडम, मैंने यह कहा था कि जो अवार्ड नेशनल अवार्डी ही होते हैं या जिसको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है उसके अंतर्गत जो भी इस प्रकार के क्राइटेरिया में आते हैं, उन सभी को इसमें, जिन्होंने भी एप्लाई किया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, साठ साल से ज्यादा उम्र के हों, उनको, हम सब को देते हैं । ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव करने वाली बात हो ।

श्री रफीक आलम : मैडम, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आप जूट प्रोडक्ट के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ? जैसे पूर्णिया में वहां जूट प्रोडक्ट जो है वह काफी है, उसके एक्सपोर्ट के बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? . . . (**व्यवधान**)

شری رفیق عالم : میڈم میں منتری مہودے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جوٹ پروڈکٹ کے بارے میں کیا قدم اٹھا رہے ہیں۔ جیسے پورنیہ میں وہاں جوٹ پروڈکٹ جو ہے وہ کافی ہے اس کے ایکسپورٹ کے بارے میں آپ کیا کاروائی کر رہے ہیں . . . مداخلت . . .

उपसभापति : जूट प्रोडक्ट से ?

श्री रफीक आलम : वह हैंडिक्राफ्ट में आता है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में काफी पैमाने पर हो रहा है । उसके एक्सपोर्ट के लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं ?

شری رفیق عالم : وہ ہینڈی کرافٹ میں آتا ہے۔ پورنیہ ڈسٹرکٹ میں کافی پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اس کے ایکسپورٹ کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں۔

श्री अशोक गहलोत : असल में, मैडम, यह तो हैंडीक्राफ्ट का सावल है जूट के प्रोडक्ट के जो हैंकयान बनते हैं उसमें पूरी छूट दे रखी है एक्साइज ड्यूटी के लिए । जो हैंकयान बनेगा जूट में उसमें जो आइटम बनेंगे उसको पूरा प्रोत्साहन मिलता है । जूट के लिए आप अलग से सवाल कर सकते हैं, अगर कोई जूट की बात है तो ।

कृषि उत्पादन की औसत दर

*524. **श्री वीरेन जे. शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी

*[ ] Transliteration in Arabic script.

—सभा में यह प्रश्न श्री वीरेन जे० शाह द्वारा पूछा गया ।